

17 आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी) लिमिटेड, करनाल (पंडित, जे.)

### आयकर संदर्भ

प्रेम चंद पंडित और भोपिंदर सिंह दिल्ली से पहले, जे.जे.

सी ओ एम ई-टीए एक्स के आयुक्त,-----आवेदक

बनाम

मैसर्स इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी) लिमिटेड, करनाल,-----प्रतिवादी।

यह। संदर्भ। 1971 की संख्या 44.

16 जनवरी 1973.

आयकर अधिनियम (1922 का XI) - धारा 10(2)(vi-बी) और 35(II) निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट तिथि के बाद नई मशीनरी प्राप्त करना, अधिग्रहण के दस साल से पहले इसे बेचना नहीं - ऐसी बिक्री का तथ्य मूल्यांकन के समय आयकर अधिकारी का ज्ञान-आयकर अधिकारी-क्या पहले धारा 10(2)(vi-बी) के तहत ऐसी मशीनरी के संबंध में विकास छूट की अनुमति देनी चाहिए और बाद में धारा 35(II) के तहत इसे वापस लेना चाहिए .

माना गया कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) के खंड (vi-बी) के अनुसार, यदि उसमें उल्लिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो निर्धारिती किसी विशेष से पहले उसके द्वारा हासिल की गई नई मशीनरी पर विकास छूट का हकदार है। उसमें निर्दिष्ट तिथि. उसमें निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह है कि मशीनरी सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पहले नहीं बेची गई है। उस वर्ष के अंत से दस वर्ष की समाप्ति, जिसमें इसे अर्जित किया गया था। यदि, मूल्यांकन के समय, मशीनरी बेची नहीं गई है, तो विकास छूट की अनुमति दी जाएगी और बाद में यदि ऐसी मशीनरी का निपटान प्रासंगिक अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है, तो छूट इस आधार पर वापस ले ली जाएगी कि पहली बार में गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी।

हालाँकि, ऐसे मामले में, जब मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, तो यह उसके ज्ञान में है कि निर्धारिती ने जो मशीनरी खरीदी थी और जिसके लिए वह विकास छूट का दावा कर रहा था, वह समाप्ति से पहले ही बेची जा चुकी है। प्रासंगिक अवधि की, तो निर्धारिती को विकास छूट नहीं दी जा सकती। करदाता को छूट की रियायत केवल इस शर्त पर दी जाती है कि वह खरीद के 10 साल की समाप्ति से पहले सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मशीनरी का निपटान नहीं करता है। आयकर अधिकारी से यह अपेक्षा करना कि वह पहले करदाता को विकास छूट की अनुमति दे और बाद में धारा 35(II) के तहत उसे वापस ले ले, जो गलतियों को सुधारने की शक्ति से संबंधित है, आयकर अधिकारी को पहले जानबूझकर गलती करने की आवश्यकता होगी। और फिर इसे सुधारें. धारा 35(II) तभी लागू होगी जब मशीनरी अपेक्षित अवधि की समाप्ति से पहले बेची गई हो, लेकिन मूल्यांकन किए जाने के बाद और जब यह तथ्य आयकर अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है, तो वह इसे सही कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत गलती इस आधार पर की गई है कि इसमें एक गलती स्पष्ट है अभिलेख।

आईटीए में पारित ट्रिब्यूनल के आदेश, दिनांक 4 जुलाई, 1970 से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया संदर्भ। निर्धारण वर्ष 1958-59 के लिए 1968-69 की संख्या 2458:-

“चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने आयकर अधिकारी को पहले नियमों के तहत पूर्ण विकास छूट की अनुमति देने और बाद में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 35 (II) के तहत इसे वापस लेने का निर्देश देने में न्यायसंगत ठहराया था, यदि लागू हो? ”

डी.एन.अवस्थी, अधिवक्ता, बी.एस. गुप्ता, अधिवक्ता, के साथ आवेदक।

जे.एस. वासु, अधिवक्ता, एस.के. स्याल, अधिवक्ता, के साथ पुनः-पोंडेंट.

निर्णय

पंडित, जे.-राजस्व के कहने पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने हमारी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है: -

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने आयकर अधिकारी को पहले नियमों के तहत पूर्ण विकास छूट की अनुमति देने और बाद में भारतीय आय की धारा 35(11) के तहत इसे वापस लेने का निर्देश देना उचित ठहराया था- कर अधिनियम, 1922, यदि लागू हो?"

(2) निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो यात्री बसें चलाती है। वर्ष 1958-59 (31 मार्च, 1958 को समाप्त लेखा वर्ष) के लिए इसका मूल्यांकन सबसे पहले 16 जुलाई, 1960 को पूरा किया गया था, लेकिन बाद में इसे अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अलग कर दिया गया, जिन्होंने निर्देश दिया कि एक नया मूल्यांकन किया जाए। यह आयकर अधिकारी द्वारा 31 अगस्त, 1967 को किया गया था। कंपनी ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (vi-बी) के तहत विकास छूट के माध्यम से 44,586 रुपये के भत्ते का दावा किया था। इसके बाद इसकी व्यावसायिक आय की गणना में 31 दिसंबर, 1957 से पहले खरीदी गई बसों के संबंध में इसे अधिनियम कहा जाएगा। हालाँकि, आयकर अधिकारी ने इस आधार पर यह छूट नहीं दी कि उक्त सभी बसें कंपनी द्वारा उनकी खरीद की तारीख से आठ साल के भीतर बेच दी गई थीं।

(3) जब मामला अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष आया, तो कंपनी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि अधिनियम की धारा 35(11) आयकर अधिकारी को ऐसे मामलों में विकास छूट वापस लेकर अपने आदेश को सुधारने का अधिकार देती है, लेकिन कानून के तहत, छूट को पहले धारा 10(2)(vi-बी) के तहत अनुमति दी जानी चाहिए और फिर अधिनियम की धारा 35(11) के तहत वापस ली जानी चाहिए। हालाँकि, अपीलीय सहायक आयुक्त ने ऐसा नहीं किया। इस निवेदन को स्वीकार करें और आयकर अधिकारी के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि जिस समय आयकर अधिकारी नया मूल्यांकन कर रहा था, उसे पता था कि बसों की तरह | कंपनी द्वारा उनकी खरीद के आठ साल के भीतर बेच दिया गया था, विकास छूट को बाद में वापस लेना होगा, और इसलिए, पहली बार में इसकी अनुमति देने और फिर बाद में इसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं था। अपीलीय सहायक आयुक्त का यह भी विचार था कि मूल्यांकन चरण में छूट को अस्वीकार करने में कोई कानूनी रोक नहीं थी, यदि आयकर अधिकारी को उस समय पता था कि बसों को उनके अधिग्रहण के आठ वर्षों के भीतर निर्धारिती द्वारा निपटाया गया था। .

(4) आयकर न्यायाधिकरण, दूसरी अपील पर, हालाँकि, उलट गया नीचे दिए गए दोनों प्राधिकारियों के समवर्ती निर्णय और इसे आयोजित किया गया धारा 10(2)(vi-बी) के संदर्भ में, विकास छूट पहले थी की धारा 35(11) के तहत अनुमति दी जाएगी और बाद में वापस ले ली जाएगी अधिनियम, यदि बाद वाला खंड लागू था।

(5) जब आयकर आयुक्त ने ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न कानून के उपरोक्त प्रश्न को इस न्यायालय में संदर्भित करने के लिए एक आवेदन किया, तो निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि मामला केवल शैक्षणिक हित का था और कानून के प्रश्न को राय के लिए इस न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा। बताया गया कि ऐसे ही एक मामले में ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था, लेकिन राजस्व उस मामले को हाईकोर्ट में नहीं ले गया था. हालाँकि, ट्रिब्यूनल इस दलील से सहमत नहीं था, क्योंकि उसका विचार था कि यह प्रश्न पूरी तरह से अकादमिक हित का नहीं था, क्योंकि यदि राजस्व कानून के उक्त प्रश्न पर सफल होता, तो 31 अगस्त, 1967 को किया गया मूल्यांकन, कायम रखा जाए, जो अन्यथा समय द्वारा वर्जित था।

(6) धारा 10(1) के तहत एक निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ और लाभ के संबंध में कर का भुगतान करना होगा। इस धारा की उपधारा (2) के तहत, इस तरह के लाभ या लाभ की गणना इस उपधारा के विभिन्न खंडों में उल्लिखित भत्ते बनाने के बाद की जानी है। खंड (vi-बी) का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

"(vi-बी) 31 मार्च 1954 के बाद अधिग्रहीत नए जहाज या नई मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, जिसका उपयोग पूरी तरह से निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विकास के माध्यम से एक राशि जहाज के अधिग्रहण या मशीनरी या संयंत्र की स्थापना के वर्ष के संबंध में छूट, के बराबर।-

(में) \* \* \* \*

(ii) 1 से पहले स्थापित मशीनरी या संयंत्र के मामले में जनवरी, 1958 का दिन, और मशीनरी के मामले में या संयंत्र, की वास्तविक लागत का पच्चीस प्रतिशत निर्धारिती को जहाज या मशीनरी या संयंत्र;

\* \* \* \*

\* \* \* \*

स्पष्टीकरण—2. \* \* \* .

बशर्ते कि इस खंड के तहत न0 भत्ता बनाया जाएगा जब तक: -

(ए) खंड (vi) के प्रयोजन के लिए निर्धारित विवरण जहाज के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है या मशीनरी या संयंत्र; और

(बी) सिवाय इसके कि जहां निर्धारिती एक कंपनी है जिसके पास बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस है, या जहां जहाज का अधिग्रहण किया गया है या मशीनरी या संयंत्र 1 जनवरी, 1958 से पहले स्थापित

किया गया है, वास्तव में दी जाने वाली विकास छूट के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर राशि संबंधित पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट की जाती है और अगले दस वर्षों की अवधि के दौरान उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आरक्षित खाते में जमा की जाती है। उपक्रम के व्यवसाय के उद्देश्य, सिवाय-

(i) लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए, या

(ii) लाभ के रूप में या सृजन के लिए भारत के बाहर प्रेषण के लिए भारत के बाहर किसी भी संपत्ति का,

और यदि ऐसा कोई जहाज, मशीनरी या संयंत्र दस की समाप्ति से पहले किसी भी समय निर्धारिती द्वारा सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है; उस वर्ष के अंत से जिसमें इसे अर्जित या स्थापित किया गया था, इस खंड के तहत दिए गए किसी भी भत्ते को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी।

(7) इस खंड के तहत, यदि कोई निर्धारिती 31 मार्च, 1954 के बाद नई मशीनरी का अधिग्रहण करता है, और! इसका उपयोग पूरी तरह से निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मशीनरी की वास्तविक लागत पर 25 प्रतिशत की सीमा तक विकास छूट निर्धारिती को दी जाएगी। हालाँकि, इस खंड के प्रावधान के तहत, यह भत्ता निर्धारिती को नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह इस प्रावधान के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित दो शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस परंतुक में आगे उल्लेख किया गया है कि यदि कोई मशीनरी निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेची या हस्तांतरित की जाती है, सिवाय इसके कि सरकार, जिस वर्ष इसे अर्जित किया गया था, उसके अंत से 10 वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, इस खंड के तहत किए गए किसी भी भत्ते को निर्धारिती को गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी।

(8) यह कहा जा सकता है कि दोनों वकील इस बात पर सहमत थे कि यात्री बसों को उपरोक्त खंड में आने वाले "मशीनरी" शब्द में शामिल किया जाएगा। यह पार्टियों का सामान्य मामला है कि इन बसों का अधिग्रहण 31 मार्च, 1954 के बाद किया गया था। और पूरी तरह से कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए

गए थे। इसके अलावा यह राजस्व का मामला नहीं है कि निर्धारिती ने उक्त खंड के परंतुक के (ए) और (बी) में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया .

इन तथ्यों पर निर्धारिती खंड में बताई गई विकास छूट का हकदार होगा। हालाँकि, कठिनाई इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई थी कि कंपनी ने खरीद के आठ वर्षों के भीतर उक्त बसों का निपटान कर दिया था। निर्धारिती का मामला यह था कि चूंकि उसने कारण (vi-बी) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, वह उक्त छूट का हकदार था और यदि बसें उनके अधिग्रहण की तारीख से आठ साल के भीतर बेची गई थीं, तो उक्त छूट दी जा सकती थी। अधिनियम की धारा 35(11) के प्रावधानों का सहारा लेकर वापस लिया जाए। दूसरी ओर, राजस्व द्वारा अपनाई गई स्थिति यह थी कि खंड (vi-बी) के परंतुक में ही यह उल्लेख किया गया था कि यदि मशीनरी दस वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेची गई थी। जिस वर्ष इसे खरीदा गया था, उस वर्ष के अंत में, इस खंड के तहत दिए गए किसी भी भत्ते को गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी और परिणामस्वरूप, कंपनी पहली बार में विकास छूट की हकदार नहीं थी।

(9) इंडियन ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इस खंड के तहत छूट एक निर्धारिती को दी गई रियायत है, लेकिन वह रियायत इसके अधीन है कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति। भत्ते का अनुदान इस खंड के परंतुक में निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर निर्भर है।

(10) चित्तूर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, चित्तूर (2) मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में, यह कहा गया था कि विधानमंडल ने विकास पर छूट देने का निर्देश दिया था जिन शर्तों का उल्लेख किया गया था! खंड (vi-बी) में, एक शर्त यह है कि यदि निर्धारिती ने मशीनरी को उस वर्ष के अंत से दस साल की समाप्ति से पहले सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो वह ऐसी छूट खो देगा।

(11) इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि निर्धारिती धारा 10(2) (vi-बी) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो वह विकास छूट भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं है।

(12) हमें संबोधित तर्क प्रावधान के अंतिम भाग से संबंधित हैं, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है: - "और यदि कोई ऐसी ..... मशीनरी .... निर्धारिती द्वारा उस वर्ष के अंत से दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, जिसमें इसे अर्जित किया गया था .... इस खंड के तहत दिए गए किसी भी भत्ते को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी। निर्धारिती का तर्क था कि उपरोक्त वाक्य के अनुसार, भत्ता पहले दिया जाना था और यदि संबंधित अवधि की समाप्ति से पहले मशीनरी बेची गई थी, तो वह भत्ता गलत तरीके से दिया गया माना जाएगा। हालाँकि, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं, जिसमें, जिस समय मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा था, उसे पता चला था कि बसें, जो कंपनी ने 31 मार्च, 1954 के बाद खरीदी थीं, और मूल जिस आधार पर वह विकास छूट का दावा कर रहा था, वह संबंधित अवधि की समाप्ति से पहले ही उसके द्वारा बेच दिया गया था। सवाल यह है कि क्या इन परिस्थितियों में भी करदाता को विकास पर छूट देनी चाहिए? खंड (vi-बी) से यह स्पष्ट है कि यदि उसमें उल्लिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो निर्धारिती विकास छूट का हकदार है। उसमें निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह है कि मशीनरी उस वर्ष के अंत से 10 वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी जिसमें इसे अधिग्रहित किया गया था। यदि, मूल्यांकन के समय, मशीनरी बेची नहीं गई है, तो छूट की अनुमति दी जाएगी और बाद में यदि संबंधित अवधि की समाप्ति से पहले मशीनरी का निपटान किया जाता है, तो छूट इस आधार पर वापस ले ली जाएगी कि प्रथम दृष्टया गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी। लेकिन ऐसे मामले में जहां मूल्यांकन के समय, पार्टियों का यह सामान्य मामला है कि मशीनरी अपेक्षित अवधि की समाप्ति से पहले बेची गई थी, तो निर्धारिती को विकास छूट नहीं दी जाएगी। इन परिस्थितियों में कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है, क्योंकि यह रियायत निर्धारिती को इस शर्त पर दी जाती है कि वह खरीद के 10 साल की समाप्ति से पहले सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मशीनरी का निपटान नहीं करता है।

यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करता है तो जाहिर तौर पर वह इस धारा के तहत भत्ते का हकदार नहीं है। मूल्यांकन के समय रिबेट की अनुमति देने का कोई मतलब नहीं है, जब मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष यह स्वीकार किया जाता है कि मशीनरी वास्तव में प्रासंगिक अवधि की समाप्ति से पहले बेची गई है। निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति में आयकर अधिकारी को पहले तो छूट देनी चाहिए और फिर अगले ही पल धारा 35(11) के प्रावधानों का सहारा लेकर उसे वापस ले लेना चाहिए। अधिनियम। धारा 35 का प्रासंगिक भाग है:-

"गलती का सुधार।-(1) आयुक्त या अपीलीय सहायक आयुक्त, अपील में या आयुक्त के मामले में, धारा 33-ए के तहत संशोधन में उनके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से चार साल के भीतर किसी भी समय कर सकते हैं। और आयकर अधिकारी किसी भी मूल्यांकन आदेश या रिफंड आदेश की तारीख से चार साल के भीतर किसी भी समय, अपने स्वयं के अनुरोध पर अपील, पुनरीक्षण मूल्यांकन या रिफंड के रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधार सकता है। होगा और उसी अवधि के भीतर ऐसी किसी भी गलती को सुधारेगा जो किसी निर्धारिती द्वारा उसके ध्यान में लाई गई है:

\* \* \* \* \*

(11) जहां धारा की उपधारा (2) के खंड (vi-बी) के तहत मूल्यांकन के किसी भी वर्ष में जहाज, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में एक निर्धारिती को विकास छूट के माध्यम से पूर्ण या आंशिक रूप से भत्ता दिया गया है। 10, और बाद में उस वर्ष के अंत से दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय जिसमें जहाज का अधिग्रहण किया गया था या मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया गया था-

(i) जहाज, मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या स्थानांतरित किया जाता है; या

(ii) निर्धारिती उस खंड के तहत आरक्षित खाते में जमा की गई राशि का उपयोग करता है-

(ए) लाभांश या मुनाफे के माध्यम से वितरण के लिए; या

(बी) लाभ के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी संपत्ति के निर्माण के लिए; या

(सी) किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो इसका उद्देश्य नहीं है  
उपक्रम का व्यवसाय;



मूल रूप से अनुमति दी गई विकास छूट को गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी जाएगी, और आयकर अधिकारी, इस अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, संबंधित वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की फिर से गणना करने के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि पुनः गणनाकर्ता एक सुधार कर रहा हो इस धारा के अर्थ के भीतर रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती होने पर, और उप-धारा (1) के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, उसमें निर्दिष्ट चार साल की अवधि उस वर्ष के अंत से मानी जाएगी जिसमें स्थानांतरण होता है या पैसे का इतना उपयोग किया गया है।”

(13) यह खंड, जैसा कि देखा जाएगा, "गलती के सुधार" की बात करता है। आयकर अधिकारी को जानबूझकर गलती क्यों करनी चाहिए और फिर इस धारा के तहत उसे सुधारना चाहिए? फिर, वर्तमान मामले की तरह, राजस्व को सीमा के प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धारा 35(11) के तहत, 1 गलती को सुधारने के लिए चार साल की अवधि की गणना वर्ष के अंत से की जानी है जिसमें मशीनरी का स्थानांतरण होता है। मौजूदा मामले में, बसें 16 जुलाई, 1960 और 31 दिसंबर, 1965 के बीच बेची गई थीं, और इसलिए, इस धारा के तहत गलती को सुधारने की सीमा शायद खत्म हो सकती है। यदि सीमा का बिंदु राजस्व के विरुद्ध तय किया जाता है, तो एक अवैधता कायम हो जाएगी और राजस्व को नुकसान होगा। इसलिए, निर्धारिती के तर्क को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप विकास छूट दी जाएगी, जहां इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि बसें संबंधित अवधि की समाप्ति से पहले बेची गई थीं। धारा 35 तभी लागू होगी जब बसें अपेक्षित अवधि की समाप्ति से पहले बेची गई हों, लेकिन मूल्यांकन किए जाने के बाद और जब उस तथ्य को आयकर अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, तो वे गलती को सुधार सकते थे यह खंड इस आधार पर कि रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती थी। निर्धारिती के तर्क के अनुसार, वर्तमान मामले में, आयकर अधिकारी को पहले विकास छूट की अनुमति देकर गलती करनी चाहिए और फिर धारा 35 के प्रावधानों का सहारा लेकर इसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और अंततः बार के कारण विफल हो जाना चाहिए। सीमा का अंतः इस विवाद में कोई दम नहीं है।

(14) इसलिए, मैं राजस्व के पक्ष में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दूंगा। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

दिल्लों, जे.-में सहमत हूँ।

---

बी.एस.जी

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए एहताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावली के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव  
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,  
हरियाणा

26 आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी) लिमिटेड, करनाल (पंडित, जे.)